

लोकसभा ने मणपुर में खेल विश्वविद्यालय स्थापति करने के लिये वधियक पारति कथिा

चर्चा में क्यों?

खेल शक्तिषा, अनुसंधान और प्रशक्तिषण प्रदान करने के लयि मणपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधति एक वधियक हाल ही में लोकसभा में ध्वनमित से पारति कर दयिा गया । राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय वधियक (SPORTS BILL) , 2018, 31 मई को जारी एक अध्यादेश को प्रतस्थापति करेगा । यह वधियक पछिले साल अगस्त में लोकसभा में पेश कथिा गया था लेकिन इसे पारति नहीं कथिा जा सका था ।

प्रमुख बिदि

- खेल प्रशक्तिषण और शोध को बढ़ावा देने के लयि 524 करोड़ रुपए की लागत से मणपुर में खेल विश्वविद्यालय स्थापति कथिा जाएगा ।
- वधियक को इससे पहले लोकसभा में अगस्त 2017 में पेश कथिा गया था, लेकिन इसे पारति नहीं कथिा जा सका था । इसलयि सरकार को एक अन्य अध्यादेश जारी करना पड़ा था।
- प्रस्तावति विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद देश में खेल के विभिन्नि क्षेत्रों जैसे – खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन प्रशक्तिषण आदि में व्याप्त अंतर को समाप्त करने में सहायता मिलेगी ।
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय वधियक, 2018 के तहत मणपुर खेल विश्वविद्यालय के पास संबंधति क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र जारी करने की शक्ति होगी ।

वधियक के मुख्य प्रावधान

- विश्वविद्यालय का कुलपति एक खिलाड़ी को बनाया जाएगा जबकि इसकी अकादमिक परिषद में खेल से जुड़े लोग शामिल होंगे।
- यह वधियक मणपुर में एक विशेष विश्वविद्यालय स्थापति करने के लयि लाया गया है, जो खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल प्रशक्तिषण के क्षेत्रों में खेल शक्तिषा को बढ़ावा देने के लयि अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा ।
- इसके अलावा, प्रस्तावति विश्वविद्यालय सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाकर चुनदि खेल विषयों के लयि राष्ट्रीय प्रशक्तिषण केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा ।
- अन्य प्रावधानों के अलावा यह वधियक देश भर में 'बाह्य कैपस' स्थापति करने के लयि विश्वविद्यालय को सशक्त बनाने का प्रस्ताव करता है ।
- वधियक के उद्देश्यों में कहा गया है कि 'अकादमिक कार्यक्रमों और शोध के अलावा विश्वविद्यालय और इसके बाहरी कैपस भी उच्च श्रेणी के एथलीटों, खेल अधिकारियों, रेफरी तथा अंपायरों को प्रशक्तिषण प्रदान करेंगे और खेल की विभिन्नि विधाओं में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में विकसिति होंगे।'
- विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय संस्थान बनाने तथा पाठ्यक्रम, अनुसंधान सुविधाओं और प्रयोगशालाओं के विकास के लयि सरकार ने दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों- कैनबरा विश्वविद्यालय और विक्टोरिया विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कथिा हैं।

खिलाड़ियों को दी जाएगी सभी प्रकार की मदद

- देश के सभी पदक विजितिओं को राष्ट्रीय खेल विकास कोष से आर्थिक मदद प्रदान की गई है, इस कोष में सभी नागरिक योगदान दे सकते हैं ।
- सरकार द्वारा खिलाड़ियों के भोजन और अन्य विभिन्नि खर्चों के लयि भत्ते के अलावा मासिक वेतन भी प्रदान कथिा गया है । सरकार ने खेल प्रशक्तिषकों के वेतन में भी वृद्धि की है ।
- खेल टूर्नामेंट द्वारा युवा प्रतिभाओं का पता लगाने के लयि एक मंच प्रदान कथिा गया है और ऐसे कार्यक्रमों को व्यवस्थिति करने हेतु सांसदों के लयि एक विशेष निधि तयि होनी चाहयि ।

खेल क्षेत्र में काफी कुछ कथि जाने की ज़रूरत

- 1928 से लेकर 1980 के बीच भारत को केवल आठ पदक मिले और ये सभी पदक हॉकी में प्राप्त हुए थे । ऐसा इसलयि है कि खेल संघों को आवंटति धन का उचित उपयोग नहीं कथिा जाता है ।
- स्कूल से ही खेल शक्तिषा अनिवार्य की जानी चाहयि । यदि आवश्यक हो तो चुनाव खर्चों से धन कम कथिा जाए और खेल पर अधिक खर्च हो क्योंकि हमारे खिलाड़ी तब तक विश्व कप नहीं जीत सकते जब तक उन्हें पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं मिलति।
- भारत के पूर्वी हिस्से को सरकार ने उपेक्षिति कर दयिा है । खेल बजट में बड़ी वृद्धि की आवश्यकता है। भारत का खेल बजट 2,000 करोड़ रुपए का है, जबकि ब्रिटेन का खेल बजट 9,000 करोड़ रुपए तथा अमेरिका का 12,000 करोड़ रुपए का है ।

- दूरदर्शन ने केवल दो या तीन खेलों पर ध्यान केंद्रित किया है और अन्य खेलों को उपेक्षित किया है। वजिजापन की मांग सभी खेलों के लिये की जानी चाहिये।
- चीन ने 1993 में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्तमान में यहाँ 20 शीर्ष श्रेणी के खेल विश्वविद्यालय हैं। इस लहजा से हम चीन से 25 वर्ष पीछे हैं।
- क्रोएशिया की आबादी 40 लाख है जो उन लोगों के बराबर है जिनका नाम असम के एनआरसी में नहीं है। लेकिन क्रोएशिया ने महान फुटबॉल खिलाड़ियों को उत्पन्न किया है और हम ऐसा करने में असफल रहे।
- हमारे देश में कार रेसिंग के लिये भी आधारभूत संरचना होनी चाहिये। कॉर्पोरेट सोशल रसिपॉन्सबिलिटी (CSR) और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MOLAD) के फंड को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिये भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- उम्मीद है कि क्रिकेट भविष्य में देश में अधिक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किये जाएंगे। सरकार को नई खेल नीति तैयार करनी चाहिये क्योंकि 2001 में बनाई गई खेल नीति काफी पुरानी हो चुकी है।

और पढ़ें : [मणिपुर में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lok-sabha-passes-bill-to-set-up-sport-versity-in-manipur>

